

विकसित भारत समाचार

वर्ष : 11 | अंक : 199 | गुवाहाटी | बुधवार, 19 फरवरी, 2025 | मूल्य : 10 रुपए | पृष्ठ : 8 | VIKSIT BHARAT SAMACHAR | Regd. RNI No. ASSHN/2014/56526

भारत के 50 प्रतिशत लोग
शेख हसीना के रहने से नाराजबिप्लब शर्मा आयोग की रिपोर्ट ने कांग्रेस
सरकार के भ्रष्टाचार को किया उजागर

पेज 2 | पेज 3 | पेज 5 | पेज 7

गुरुदासपुर में पुलिस कर्मी के घर पर
धमाका, बब्बर खालसा ने ली जिम्मेदारीचेन्नई में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स
चैम्पियनशिप का हुआ भव्य आगाज

विकसित भारत के लिए चार इंजन वाला बजट : मेघवाल



गुवाहाटी (हिस.)। केंद्रीय कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्रीय बजट एक रोडमैप है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 चार प्रमुख इंजनों पर आधारित है—कृषि विकास, निवेश, एमएसएसएस को बढ़ावा देने और नियर्थावां और औद्योगिक विकास। केंद्रीय मंत्री मेघवाल मंत्रलाल को राजधानी दिसपुर स्थित लोकनिमण विभाग कार्यालय हाल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहला इंजन कृषि विकास है, जिसमें पूर्वोत्तर और असम के किसानों

के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। दूसरा इंजन निवेश है, जो सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश को प्रोत्साहित करेगा। सरकार रेलवे, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश कर रही है, जिससे रोजगार और अधिक गतिविधियों बढ़ेंगी। तीसरा इंजन एमएसएसएस सेक्टर को मजबूत करने के लिए है, जिसमें कृषि की सीमा बढ़ाने और नई अप्रभारपां लागू करने जैसे कदम उठाए गए हैं। चौथा इंजन नियर्थावां को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि भारत इंडस्ट्री 4.0-

-शेष पृष्ठ दो पर

सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से की मुलाकात, मेगा बिजनेस समिट के लिए मार्गदर्शन मांगा

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा ने गृह मंत्री शाह को गुवाहाटी में आयोजित दो दिवसीय मेगा बिजनेस समिट को सफल बनाने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवास कराया, जिसमें देश के भूती और बाहर से भागीदारी और प्रयुक्त क्षेत्रों में निवेश आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से मार्गदर्शन भी मांगा। शाह ने समिट को सफल बनाने के लिए डॉ. शर्मा के अथक प्रयासों की सराहना



की और आशा व्यक्त की कि यह मेंगा इवेंट ने केवल भारी निवेश लाएगा, बल्कि असम को भारत के विकास इंजन और निवेश के लिए आकर्षक गतिका के रूप में वैश्विक मानचिक पर भी लाएगा। डॉ. शर्मा ने शाह के साथ बातचीत की ओर उहाँगे गमोद्धा भेट किया। मुलाकात 30 मिनट से अधिक समय तक चली। दो दिवसीय एडवेंचर असम 2.0 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नेर्द मोदी 25 फरवरी को करेंगे। बाद में, एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि आज नई दिल्ली में, मुझे माननीय गृह मंत्री श्री @amitshah जी से #AdvantageAssam2 के लिए उनका मार्गदर्शन लेने का सम्मान मिला।

कछार में भारत-बांग्लादेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकाकार भारत बनेगा सीमा पर रात्रि कपर्फ्यू लागू दुनिया का सबसे ताकतवर देश : प्रमोद बोड्डे

कछार (हिस.)। राज्य के कछार जिले के प्रशासन ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर रात्रि कपर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना और तस्करी को रोकता करने के लिए है। जिसमें कृषि की सीमा बढ़ाने और नई अप्रभारपां लागू करने जैसे कदम उठाए गए हैं। चौथा इंजन नियर्थावां और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा कि पहला इंजन कपर्फ्यू लागू करने के लिए रखा गया है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए, कछार के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यादव ने सीमा क्षेत्र में सख्त प्रतिवंध लगाने का आदेश जारी किया। कानून और व्यवस्था के मुहुरे पर चिंताओं का हलात देते हुए, बीएसएसएस की धारा 163 के तहत लागू किए गए निर्णय में उप्रवादी तत्वों की बुस्पैष और वस्तुओं और मवेशियों के



-शेष पृष्ठ दो पर

महाकुंभ नगर (हिस.)। गुवाहाटी से हेलीकॉर्टर से तीर्थराज प्रयाग आए बोडोइंड ट्रेटोरेसिल काउंसिल (बीटीआर) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) बोडोइंड ट्रेटोरेसिल के साथ मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ के साथी बने। उन्होंने त्रिवेणी संगम में मुष्य की द्वितीय लगाकर जगकल्याण की कामना की। उन्होंने गोवर्धन मंद पुरी पांत्राधार जगद्गृह शक्तिराचार्यी अधोक्षजानांदे देवतीर्थ के शिखिर में आदि शक्तिराचार्य के चरण पादका की सूना अंचना की। उन्होंने कहा कि अब वर्ष एक गोवर्धन सीधे दूर से जुड़ा है, इसलिए यह दियाना तक जाता है। यह भविष्य में और बढ़ता जाएगा। महाकुंभ को देखे या जाने बिना, कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने यह बातें हिन्दुस्थान समाचार प्रतिनिधि से एक विशेष वार्ता के दौरान कहा। -शेष पृष्ठ दो पर

महाकुंभ में कई जगह स्नान के लायक भी नहीं पानी, सीपीसीबी की रिपोर्ट से हड्डकंप

नई दिल्ली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दीर्घावन पर विभिन्न स्थानों पर फौलकल कोलाइफोम का स्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर जल स्नान के लायक नहीं हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने रिपोर्ट दायर कर सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल को यह जानकारी दी। दरअसल, सीपीसीबी के अनुसार, फौलकल कोलाइफोम सीवेज प्रदूषण का संकेतक है। इसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल को यह जानकारी दी। मात्र 100 मिलीलीटर पानी में 2,500 यनिट तक होनी चाहिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में सीवेज प्रवाह को रोकने के लिए यह महाकुंभ नहीं रहा, यह मृत्यु कुंभ में बदल गया है। हाल ही में महाकुंभ के



यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है : ममता कोलकाता (हिस.)। राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री लाल यादव के बाद प्रशिम बगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी महाकुंभ को लेकर विवाहित बयान दिया है। ममता ने प्रयागराज में गंगा और हिन्दुओं की आस्था के अपार्व महाकुंभ को लेकर विवाहित बयान दिया है। ममता ने अपार्व महाकुंभ नहीं रहा, यह मृत्यु कुंभ में बदल गया है। हाल ही में महाकुंभ के -शेष पृष्ठ दो पर

रणवीर इलाहाबादिया को एससी की फटकार, कहा-इनके दिमाग में गंदगी भरी है, यूट्यूबर का पासपोर्ट जब्त करें

गुवाहाटी। अपनी ब्रिटिश पाली के पारिस्थानिक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आएसएसई) से कथित संबंधों को लेकर उठे विवाद के बीच कांग्रेस संसद गैरव गोगोई ने मंगलवार को दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को डर है। जब याचिकार्ता के वकील ने बताया कि कई गंगों और इन गण्डों और केंद्रीय प्रदूषण प्रयोग के लिए रिपोर्ट दायित्व नहीं की। अब वह दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिवसीय घटनाक्रम को संकेतक है। इसकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल को यह जानकारी दी। मात्र 100 मिलीलीटर पानी में 2,500 यनिट तक होनी चाहिए। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में सीवेज प्रवाह को रोकने के लिए यह महाकुंभ के संकेतक है। इसकी में सीवेज प्रवाह को रोकने के लिए यह महाकुंभ के संकेतक है। -शेष पृष्ठ दो पर

उद्दीपन के लिए इलाहाबादी द्वारा साथ रेना के बीच इंडियाज गॉट लेटेंट में रेटेंटेस की आस्था के अपार्व महाकुंभ को लेकर भाव्य बदल गया है। कोर्ट ने कहा कि इनके दिमाग में गंदगी भरी है। ऐसे व्यक्ति का केस हम क्या सुनें। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इनके (रणवीर इलाहाबादिया) -शेष पृष्ठ दो पर

अरब में यूक्रेन जंग पर रूस-अमेरिका में वार्ता जेलेंस्की से बातचीत को तैयार हुए पुतिन



गुवाहाटी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। यह घोषणा तब आई है जब अमेरिका और रूसी राजनीतिक सञ्चारी अब दोनों देशों में सुधार और यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति पर बातचीत शुरू की। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व अमेरिकी विदेश मंत्री मार्टिन रुबिनो ने किया, जबकि रूसी पक्ष के नेतृत्व विदेश मंत्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा किया गया है।

उद्दीपन की नीति के तहत आगे बढ़ रही है। पिछलाल ग्रेडेश को लेकर भाव्य रिपोर्ट से ठीक एक दिन पहले, मं

संपादकीय

वक्फ पर सियासी बवाल

भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र है। कानून का राज है, तत्स्थ और विवेकी न्यायपालिका है। इस देश में वक्फ बोर्ड भी है। वह जिस इमारत, जमीन, गांव और सैकड़ों साल पुराने मंदिर और मठ की तरफ अपनी उंगली उठाता है, तो वह उसकी संपत्ति मान ली जाती है। बेशक विवादों के लिए एक ट्रिव्यूनल भी है, लेकिन उसमें 40,950 से अधिक मामले अब भी लंबित पड़े हैं। 19942 मामले ऐसे भी हैं, जो मुसलमान वादियों ने ही वक्फ के खिलाफ कर रखे हैं। देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक वक्फ बोर्ड के अधीन 9.40 लाख एकड़ जमीन है। आर्थिक विश्लेषण किया जाए, तो उस जमीन से 1.25 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए। वक्फ जमीन के कब्जे बाज

वरक जमीन के कब्जेबाज सिर्फ 200 करोड़ रुपए की आमदनी ही मानते रहे हैं। क्या यह किसी घोटाले की ओर संकेत करता है? क्या ऐसी निरंकुशता और कानूनहीनता किसी संवैधानिक देश में स्वीकार्य हो सकती है? यह बुनियादी आधार है, जिस पर वरक बोर्ड के नए कानून, नए नियमों और पूरी तरह कानूनी प्रारूप के लिए मौजूदा कानून में संशोधन अनिवार्य है। भारत में सेंट्रल और राज्य के कुल 30 बोर्ड कार्यरत हैं। लाखों संपत्तियां वरक बोर्ड के अधीन हैं, लेकिन आम मुसलमान के लिए कोई फायदा नहीं। आम मुसलमान के लिए कोई अधिकृत अस्पताल नहीं। आधुनिक स्कूल, कॉलेज नहीं हैं। जरूरतमंद के लिए आर्थिक मदद की कोई विशेष योजना नहीं है। मुसलमानों की स्थिति पर सच्चर कमेटी की रपट में भी वरक पर कई गंभीर और तत्त्व टिप्पणियां की गई थीं। दरअसल एक ताकतवर तबके के वरक बोर्ड के जरिए लाखों संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 के तहत न तो किसी के मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, न मजहबी आजादी को 'गुलाम' बनाया जा रहा है और न ही सरकार किसी मस्जिद, इबादतगाह, दरगाह, मदरसों, कबिस्तानों आदि पर कब्जे के मांसपेश पाले

पर कई गोमार और तल्खी अपाणिया की गई थीं। दरअसल एक ताकतवर तबके के वक्फ बोर्ड के जरिए लाखों संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 के तहत न तो किसी के मौलिक अधिकार छीं जा रहे हैं, न मजहबी आजादी को 'गुलाम' बनाया जा रहा है और न ही सरकार किसी मस्जिद, इबादतगाह, दरगाह, मदरसों, कब्रिस्तानों आदि पर कब्जे के मंसूबे पाले बैठी हैं। संविधान और प्रभावशाली न्यायपालिका के देश में यह करना संभव भी नहीं है। मुस्लिम सांसद औरैसी साख्यों और अतीत की घटनाओं के आधार पर यह साबित करें कि सरकार वक्फ संशोधन कानून इसलिए बनाना चाहती है, ताकि मुसलमानों की वक्फ परिसंपत्तियों को हड़पा जा सके। मुस्लिम और उनके बोत बैंक पर जिंदा राजनीतिक दलों के नेता औसत मुसलमान को भड़काने और आंदोलित करने की सियासत कर रहे हैं, लिहाजा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड्डे ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की 655 पन्नों की रपट को 'फर्जी' करार दिया है। उसे

अलाकनानंत्रक, सावधान-वरिया आरप्रक्रिया-विरोधी भी माना है। लोकतांत्रिक भारत में 'असावैधानिक' तो यह है कि वक्फ संपत्तियों का कोई 'सेंट्रल डाटा' ही उपलब्ध नहीं है। वक्फ वाले तो संसद भवन की जमीन को भी वक्फ की संपत्ति मानते हैं। शुक्र है कि अभी राष्ट्रपीठ भवन उनकी निगाहों से बचा हुआ है। वक्फ को लालकिला और कुतुब मीनार की जमीन को भी वक्फ की संपत्ति मानने में कितना वक्त लग सकता है? हैरान व्यवस्था है कि वक्फ द्रिव्यूनल के फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती! अब संशोधित विल के अनुसार द्रिव्यूनल के फैसले को राजस्व अदालत, सिविल कोर्ट और उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ में ऐसे कई बिंदु और व्यवस्थाएँ हैं, जिन्हें कानून के दायरे में लाना संसद का दायित्व है।

कृष्ण
अलग

कॉमन सैंस का सवाल है।

वे दोनों निहायत ही कॉमन आदमी थे। लिहाजा तिकड़म से भी दूर थे। किसी भी स्तर के लीडर के साथ उनकी कोई भी सैटिंग नहीं थी। यहाँ तक कि अफसरसाही में भी उनका कोई टांका फिट नहीं था। अपने हर काम के लिए उन्हें लाईन में लगना पड़ता था। वे बस टिकट लेने के लिए भी लाईन में लगते थे और पीछे से आए लोग उनके आगे खड़े होकर उन्हें बार-बार पीछे धकेल देते थे। बसों में आरक्षित सीटों पर दूसरी किस्म के यात्रियों को आराम से टार्गे फैलाकर यात्रा करते देखना उनकी नियति में शुभारथा। वे चलती बस में हैंडल पकड़कर झुलते हुए अक्सर यह सोचा करते थे कि वह दिन कब आएगा जब हर बस में यह लिखा होगा कि 'सारी सीटें कॉमन आदमी के लिए आरक्षित हैं।' एक दिन उनके कान में उड़ते-उड़ते कहीं से यह खबर पहुंची कि 'सरकार अब सारे फैसले कॉमन आदमी के हितों को सामने रख कर लेगी।' पहले तो उन्हें इस खबर पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने अखबारों में इस बाबत खबर पढ़ी तो उनकी हैरत और बढ़ी। दोनों चंकि कॉमन आदमी थे, लिहाजा बौद्धिक और वैचारिक रूप से भी कॉमन थे। उन्होंने अपने हिसाब से इस खबर का विश्लेषण करना शुरू किया। पहले कॉमन आदमी से दूसरे कॉमन आदमी से कहा- इसका मतलब है कि सरकार को अब पता चल गया है कि कॉमन आदमी का भी कोई हित होता है? दूसरे ने कान खुजलाते हुए कहा कि, 'लेकिन सरकार को यह बात किसने बताई होगी कि कॉमन आदमी का भी कोई हित होता है?' पहले ने इस पर अनभिज्ञता जताते हुए कहा- 'जरूर सरकार को इस बारे कोई इलम हुआ होगा या कोई आकाशवाणी सरकार के कानों ने सुनी होगी, वरना अपनी समझ के मुताबिक तो इस व्यवस्था में कॉमन आदमी नसीब में सिर्फ धक्के खाना ही है।' दूसरे आदमी ने कहा देर सबाद कहा, 'लेकिन मेरी कॉमन यही कहती है कि जिस तरह राजनाम की कोई चीज होती है, उस उनके लिए 'कॉमन मैन का हित' की चीज जरूर होती होगी।' पर आदमी ने भी इस सवाल पर कुछ चिंतन मुद्रा बनाए रखी और पिछे 'अगर मैं अपनी कॉमन सैंस पर करूं तो नेताओं के लिए राष्ट्रहित कॉमन आदमी के हित दोनों बेची जैं हैं। नेता राष्ट्रहित से भी बचा करते आए हैं और कॉमन आदमी से भी।' दूसरे आदमी ने पहले इस विचार को सिरे से खारिज कहा- 'जब सरकार कॉमन आदमी हित सामने रखने की बात कह जरूर व्यवस्था में कुछ नया हो जाएगा।' पहले आदमी ने खिल्ली हुए कहा, 'क्या तुम समझते हो सरकार अब पैट्रोल, डीजल और वस्तुओं की कीमतें बढ़ाने से पहले कॉमन आदमी से पूछा करेगी? को अंजाम देने से पहले कॉमन को विश्वास में लिया करेगी? राजने से पहले कॉमन आदमी उसमें हिस्सा पती रखा करेगी? आदमी के काम बिना रिश्वत निपटाना अधिकता के आधार पर हुआ। दूसरे आदमी ने पहले आदमी वीच में काटते हुए कहा, 'अगर कॉमन आदमी के लिए इतना सरकार ने लग गई तो फिर अपने लिए करेगी? अगर कॉमन आदमी वीआईपी सुविधाएं देने लग गई वीआईपी और कॉमन मैन के ढाँफ कर होगा। वीआईपी को फिर डालेगा?' अब ताव में आने के पहले आदमी की थी।'

ललित गर्ग

एआई से बदलती दुनिया के
चमत्कार वरदान से कम नहीं है,
लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियां एवं
खतरे इसे अभिशाप में भी बदल
सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि
इसके उपयोग के संदर्भ में कोई
वैश्विक ढांचा एवं नियंत्रण का
केन्द्र एवं नीति बने। क्योंकि
एआई के दुरुपयोग के खतरे
किसी से छिपे नहीं। अभी एआई
का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण
में ही है, लेकिन उससे पैदा होने
वाली कई चुनौतियां एवं खतरों ने
सिर उठा लिया है।

कोण

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री

के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट दे दी है और इसके सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जिसपर देश को खोखला कर दिया है और वह देश के इस बुराई से मुक्त करने के लिए पूरे मनोयोग रख काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इन दृढ़निश्चय के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता रहा? इसकी तरह फैलता जा रहा है। केंद्री की भाजपा सरकार हो या राज्यों में विपक्षी दलों के सरकारें, सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े दावे वादे करती रही हैं, किंतु यह समस्या सुरक्षा वें मुंह की तरह विकराल होती जा रही है। करपाणी परसेशन इंडेक्स-2024 की भ्रष्टाचार की सूची वाले देशों में भारत 96वें पायदान पर पहुंच गया है। साल 2023 में भारत की रैंक 93 थी। भारत इस सूची में पड़ोसी देशों की ज्यादा बुंदेल हालत पर कुछ राहत महसूस कर सकता है। भ्रष्टाचार की इस सूची में भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 135 नंबर पर और श्रीलंका 12

पेरिस में हुए दो दिवसीय एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) प्रबल्लास परियार्थ त्रिमास के लिए आर्टिफिशियल

एक्शन सामैट न जहा दुनिया के लिए आटाफशल इंटेलिजेंस के महत्व को उजागर किया, वहीं यह भी साफ कर दिया कि इस मामले में होड़ के बावजूद सभी देशों का आपसी तालमेल बनाए रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है। एआई से बदलती दुनिया के चमत्कार वरदान से कम नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी चुनौतियाँ एवं खतरे इसे अभिशाप में भी बदल सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि इसके उपयोग के संदर्भ में कोई वैश्विक ढांचा एवं नियंत्रण का केन्द्र एवं नीति बने। क्योंकि एआई के दुरुपयोग के खतरे किसी से छिपे नहीं। अभी एआई का उपयोग अपने प्रारंभिक चरण में ही है, लेकिन उससे पैदा होने वाली कई चुनौतियाँ एवं खतरों ने सिर उठा लिया है। लेकिन इस नई तकनीक से जीवनशैली, शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध, सेना, शासन-प्रशासन, चुनाव, व्यापार, विचार आदि में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारत एआई को लेकर बहुत उत्साहित है और दुनिया में एआई का सबसे बड़ा केन्द्र बनने को भी तैयार है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर बैठक की सह-अध्यक्षता की बल्कि अगली शिखर बैठक की मेजबानी करने की पेशकश भी करते हुए बता दिया कि भारत इस पहल को कितनी गंभीरता से लेता है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होते हुए तकनीकी विकास की दृष्टि से भी सफलता के नये झङ्गे गाड़ रहा है। एआई को लेकर भारत की सोच सकारात्मक एवं विकासमूलक है इसीलिये प्रधानमंत्री मोदी ने यह सही कहा कि इस तकनीक में दुनिया को बदलने की ताकत है, लेकिन अमेरिका की कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियों ने सूचना संसार में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। उनके एकाधिकार और उनकी मनमानी से निपटना विश्व के तमाम देशों के लिए मुश्किल हो रहा है। यदि इसी तरह का एकाधिकार एआई कंपनियों ने भी स्थापित कर लिया तो फिर समस्या गंभीर हो जाएगी। सबसे अधिक समस्या विकासशील



और निर्धन देशों को होगी, जो पहले से ही चुनिंदा तकनीकी कंपनियों के वर्चस्व तरे दबी हुई है। मोटी ने एआई तकनीक के संतुलित एवं विवेकसम्मत उपयोग एवं विकास की आवश्यकता को भी व्यक्त किया। क्योंकि यह उन्नत तकनीक बनाने वाली कुछ कंपनियां उसे अपने हिसाब से संचालित करती हुई भी दिख रही हैं। इस तकनीक का मनमाना इस्तेमाल न होने पाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावी कदम उठाने होंगे। यह एआई एकशन समिट ऐसे समय हो रही है, जब चीनी कंपनी डीपसीक दुनिया को एक जबर्दस्त झटका दे चुकी है। भारत एआई की चुनौतियों एवं खतरों को लेकर सतर्क है। क्योंकि एआई द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ बहुआयामी हैं और लगातार विकसित हो रही हैं। उदाहरण के लिए डीपफेक, जो डिजिटल मीडिया है-वीडियो, ऑडियो और चित्र-जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संपादित और हरेकफर किया जाता है, हाइपर-रियलिस्टिक डिजिटल मिथ्याकरण को शामिल करते हैं। इसका संभावित रूप से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने, सबूत गढ़ने और लोकात्मिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। जबकि डीपफेक का इस्तेमाल चुनावों जैसे कुछ मामलों में किया गया है, उनका उपयोग विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से देखा जा रहा है। डीपफेक के अलावा, एआई से जुड़े अन्य जोखिम भी हैं। इनमें गोपनीयता, पूर्वाप्रीति, पारदर्शिता, जवाबदेही और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए एआई के संभावित दुरुपयोग से

संबंधित मुद्दे शामिल हैं। भारत सरकार इन मुद्दों को सलाह और विनियमों के माध्यम से नियोजित एवं नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो पारदर्शिता, सामग्री मॉडरेशन, सहमति तंत्र और डीपेक पहचान पर जोर देते हैं ताकि जिम्मेदार एआई तैनाती सुनिश्चित हो और चुनावी अखंडता की रक्षा हो सके। यह एक सतत प्रयास है और जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक मजबूत तंत्र के विकास के साथ सक्षम होने की अपेक्षा रहेगी। एआई विकसित होता रहेगा, नये-नये करिश्माई एवं चमत्कारी आयाम उससे जुड़ते रहेंगे और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह ऐसे तरीके से हो जो सभी के लिए सुरक्षित, नैतिक और लाभकारी हो। आवश्यक बुनियादी ढाँचे, हार्डवेयर और क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमताओं के विकास में सहायता के लिए निवेश महत्वपूर्ण है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से आवश्यक पूंजी जुटाई जा सकती है। यह संयुक्त प्रयास एआई नवाचार, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकेगा और जिससे भारत एआई क्रांति में अग्रणी बन दुनिया का नेतृत्व कर सकेगा। इसी पहलू को रेखांकित करती है यह पेरिस की तीसरी एआई एकशन समिट, जिसमें दुनिया भर के 90 देशों और तमाम बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य का अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन किसी भी वजह से इसकी ग्रोथ को बेकाब होने दिया गया तो उसके परिणाम खतरनाक साबित हो सकते हैं। भारत की भूमिका को खास बनाता है इसका असाधारण टैलंट पूल, इसके बेहिनियर और वैज्ञानिक जो नाम मात्र की लागत पर बड़े-बड़े अंतरिक्ष अभियान को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में भारत की पहल बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बेहतर होगा कि केंद्र सरकार एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाकर इस तकनीक को लेकर अपनी प्राथमिकता तय करे। इनोवेशन में भारत को हर जोखिम को उठाने के लिये स्वयं को सक्षम करना होगा। एआई का समुचित लाभ उठाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।

जानकारी का न पर पहुंच क 93 थी। ज्यादा बुरी सकता है। डोसी देशों लंका 121 स्रोतों से लिया जाता है। ये सोर्स विश्व बैंक और विश्व अर्थिक मंच सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानोंद्वारा एकत्रिक जाते हैं। सीपीआई की गणना करने की प्रक्रिया की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जारी की जाने वाली सूची भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनावी जीत यहार के पैमाने पर नहीं है। मैं चुनाव जीतने यहारने के लिए भ्रष्टाचार से नहीं लड़ रहा हूं। यह मेरा मिशन है, मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दोमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। मैं इस देश को भ्रष्टाचार

केंद्रीय बजट और हमारा प्रदेश

बजट पर देश के प्रत्येक राज्य व समाज के प्रत्येक वर्ग की निगाहें टिकी रहती हैं कि उन्हें इससे क्या मिला? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक परवरी 2025 को 2025-26 का बजट लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए देश के विकास और कल्याण के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। लेकिन बिहार और असम के सिवाय किसी राज्य का विशेष जिक्र नहीं हुआ। जब बिहार में मखाना बोर्ड और असम में यूरिया संवर्यंत्र स्थापित करने का विशेष उल्लेख किया गया, तो हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्य कह उठे कि हमारे राज्य को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा। राष्ट्रीय योजनाओं व कार्यक्रमों से हर राज्य को लाभ मिलता आया है और मिलता ही रहेगा। आखिर हमारा भारत, संघीय ढांचा ही तो है। राज्यों को मिल कर ही देश बना है। देश में एक ही तो नागरिकता है। जो देश का है वह राज्यों का भी है। यहां बजट में की गई कुछ घोषणाओं का जिक्र करना जरूरी है, जिससे अन्य राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को भी बहुत फायदा मिलने वाला है। कृषि व बागवानी : प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना लागू करने की घोषणा हुई है जिसमें कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों में उत्पादकता व भंडारण बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। सिंचाई सुधार के साथ-साथ किसानों को दीर्घ व लघु अवधि के ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना से देश के 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हिमाचल प्रदेश से भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी एक जिले को चुने जाने की संभावना है। पहले भी सबसे कम विकसित जिलों की आर्थिक प्रगति के लिए चलाई गई एकांक्षी जिला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला को चुना गया था। फल व सब्जी उत्पादन व खाद्य और फल प्रसंकरण के लिए भी देश में व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश, देश के फल राज्यों में से एक है। राज्य में सेब की पैदावार सबसे अधिक होने के कारण इसे सेब राज्य की संज्ञा दी गई है। हिमाचल प्रदेश को गैर मौसमी सब्जियां उगाने की भी महारत हासिल है। ऐसे में हमारे बागवानों और सब्जी उत्पादकों को भी लाभ मिलना सुनिश्चित है। केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले ऋणों की ऋण सीमा तीन लाख से पांच लाख तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई है। हिमाचल में 10 लाख के करीब सीमांत, लघु, मझेली और बड़ी किसानी जोते हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ हिमाचल के खेती किसानों, डेयरी किसानों और यहां तक कि मछुआरे भी उठा सकते हैं। प्रदेश में 13000 के लगभग मछुआरे हैं। एमएसएमई और स्टार्टअप (सूक्ष्म और मध्यम उद्यम), एमएसएमई व स्टार्टअप के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को 2.5 व 2.0 गुणा बढ़ाया जा रहा है। उन्हें ऋण तक पहुंच बनाने के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाने की घोषणा भी हुई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए रुपए 5 करोड़ से रुपए 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ा कर 20 करोड़, उत्तम चल रहे नियर्यातक एमएसएमई के लिए रुपए 20 करोड़ के साथी ऋण की व्यवस्था की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों को भी इससे लाभ पहुंचेगा और उद्यमियों के साथ-साथ प्रदेश में युवाओं के लिए भी रोजगार बढ़ेगा। प्रदेश में इस समय 136000 उद्यम पंजीकृत हैं जिसमें 97.5 प्रतिशत सूक्ष्म, 2.37 प्रतिशत लघु और 0.28 प्रतिशत मध्यम किस्म के हैं। शिक्षा और कौशल विकास : बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने की उद्देश्य से देश में पहले से ही अटल टिकिरिंग लैब कार्यक्रम चल रहा है। अगले पांच सालों में 50000 और अटल टिकिरिंग लैब खोले जाने का प्रस्ताव है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के कई विद्यालय इस सुविधा को प्राप्त कर सकेंगे। भारतीय नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी माध्यम पाठशालाओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी जिसमें हिमाचल के भी कई स्कूलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के तहत स्कूल और उच्चर में शिक्षा के तिडिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदेश के विद्यार्थी भी लाभ में प्रवेश के लिए आगामी सीटे और मेडिकल कॉलेजों में 75000 नए प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। इससे हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलेगा। इससे हिमाचल के लिए देश में राष्ट्रीय कौशल जा रहे हैं जिससे राज्य के कर सकेंगे। स्वास्थ्य : अन्य गंभीर बीमारियों से देने के उद्देश्य से 36 जिलों बुनियादी सीमा शुल्क में है। कुछ अन्य जीवनरक्षण रियायती सीमा शुल्क के इससे रोगियों को सस्ती अगले तीन सालों में देने के उद्देश्य से 36 जिलों बुनियादी सीमा शुल्क में है। अस्पतालों में डे-केय जाहिर है कि हिमाचल के तरीके से इससे लाभान्वित कंपनियों में डिलीवरी अस्थायी कर्मचारी जिन्हें है, को प्रधानमंत्री जन उद्योग लाए जाने का प्रस्ताव दिया गया। पर्यटन : केंद्रीय बजट में इससे स्थलों को विकसित किया जाना चाहिए। राज्यों की भागीदारी भी उड़ान योजना में देश में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए केंद्र से छोटे हवाई अड्डे बनाने हैं। आशा की जानी चाहिए देवस्थलों के विकास बढ़ाने के लिए केंद्र से होंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बढ़ावा देने की भी विचाराएं बहुत ही अनुकूल हैं। वे को राहत देने वाला है।

उच्चतर में शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकों प्रदान की जाएंगी जिससे प्रदेश के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। आईआईटी में प्रवेश के लिए आगामी वर्ष 6500 अतिरिक्त सीटें और मेडिकल कॉलेजों में 10000 नई सीटें सृजित होंगी। मेडिकल कॉलेजों में आगामी पांच सालों में 75000 नए प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव है, जिससे हिमाचल प्रदेश के इच्छुक विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। इसी तरह कौशल निर्माण के लिए देश में राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र खोले जा रहे हैं जिससे राज्य के युवक भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य : केंद्रीय बजट में कैसर व अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के उद्देश्य से 36 जीवन रक्षक दवाइयों को बुनियादी सीमा शुल्क में पूरी तरह से छूट दी गई है। कुछ अन्य जीवनरक्षक दवाइयों को 5 फीसदी रियायती सीमा शुल्क की सूची में डाला गया है। इससे रोगियों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध होंगी। अगले तीन सालों में देश के प्रत्येक जिले के अस्पतालों में डे-केयर सेंटर स्थापित होंगे। जाहिर है कि हिमाचल के भी सभी जिले चरणबद्ध तरीके से इससे लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन कंपनियों में डिलीवरी के साथ जुड़े या अन्य अस्थायी कर्मचारी जिन्हें गिर वर्कस कहा जाता है, को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाए जाने का प्रस्ताव है जो अत्यंत सुखद है। पर्यटन : केंद्रीय बजट में देश में 50 पर्यटक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इसमें राज्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। उड़ान योजना में देश में 120 नए गंतव्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हेलिपैड या छोटे हवाई अड्डे बनाने का प्रावधान किया गया है। आशा की जानी चाहिए कि प्रदेश के तीर्थों, देवस्थलों के विकास व उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र से उचित सहायता प्राप्त होंगी। पहाड़ी क्षेत्रों में मेडिकल ट्रूरिज्म को बढ़ावा देने का भी विचार है। हिमाचल का स्वच्छ पर्यावरण मेडिकल अर्थात् हेल्थ पर्यटन के लिए बहुत ही अनुकूल है। केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग को राहत देने वाला है।

आप का नजराया

नजराया

धार तेज

शिमला में हेरय डेसर ने अपने हुनर की धार को अपराध में लगा दिया। यह घिनौनी वारदात है जो बता रही है कि इनसानी गिले-शिकवे कितने धातक हो सकते हैं। कुछ दिन पहले एसडीएम मंडी को खनन माफिया के प्रहार से दो-चार होना पड़ा था। ऐसे में स्थितियों के भीतर कानून व्यवस्था का माहौल लाचार दिखार्दा देता है। इन सबके बीच हम राज्य को या तो राजनीतिक भंवर में देखते हैं यै इसके दाग, उसके दागों से बेहतर साबित करने में लगे हैं। प्रदेश की प्रशंसा की धार भी तेज है और काम का सलीका भी तेज है। कहना न होगा कि प्रदेश में सबसे अधिक पृष्ठ हार यहां इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि गर्दने बताती हैं कि कितना वजन उठा सकती है, लेकिन समाज की गर्दनों पर चट्टे की सवारी नजर नहीं आती। यहां अब एक खरीद-फरोखन की धार है। एक अजीब नशे का उपभोक्तावाद है, जहां आने वाली पीढ़ी के खिलाफ माफिया की धार तेज है। कभी हिमाचल में जनता पैदल चलती थी। पथरों के रस्ते पर कोई प्याऊ मिल जाता था। इनसानी सफर में प्यास को बुझाने का सामाजिक दायित्व अंगीकार होता था। अब हम स्वीकार कर चुके हैं कि चट्टा यूं ही आता रहेगा, इस रंग भरे समाज के सामने। हमारे सामने पूरी व्यवस्था एक ऐसी धारा है, जहां हर कोई अपनी धार तेज कर रहा है। कभी देखना जेसीबी की धार जिसने तमाम ‘धारे’ नोच लीं। पहाड़ को समतल बनाने की धार कितनी प्रभावशाली होगी और यही नहीं, अब तो नदियों की धाराको मोड़ने की धार भी हमने पैदा कर ली। गगल अभी एयरपोर्ट विस्तार में उड़ाना नहीं, लेकिन एक बाहरी संसार अपनी-अपनी धार में बसने लगा है। टीलों पर खड़े लोग खड़ी में जमीन टटोल रहे हैं, पानी को फांसी देने का मुकदमा नंगे पहाड़ की अदालत में। गगल-चैतू भार्ग पर कुछ साल पहले बरसात की धार और धारा ने जिन खड़ी को समुद्र बनाया था, वहां कायमत को रोकने के लिए एक बस्ती बसाई जा रही है। खड़ी के उसूल और एनजीटी के कबूल से कहीं दूर अगर धार तेज है, तो चैतू की इस कालोनी के लिए खड़ी से लड़ते पथरों की अनूठी किस्मत देख लीजिए। आश्चर्य यह कि पीने के पानी के लिए लड़ते लोग शिमला जिला के एसडीएस को अपनी धार बता रहे हैं। क्या वर्तमान सिस्टम के किसी अधिकारी में कोई धार बच्ची रह सकती है। प्रदेश में ट्रैफिक जाम में कुम्हलाई व्यवस्था की धार क्यों नहीं हो सकती है। राज्य के बाईर एरिया में घुसते नशे के व्यापार के खिलाफ कानून-व्यवस्था की धार क्यों नहीं हो सकती। धार शिक्षा के पाठ्यक्रम में, नवाचार के क्रम में और रोजगार के दम में क्यों नहीं हो सकती। हमने धार को गलत बना दिया, प्रदेश का प्रभाव और प्रभुत्व बना दिया। अगर पूरे प्रदेश के अतिक्रमण का हिसाब लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा कि हर गांव से शहर तक, कूहल से नदी तक और कायदे से कानून तक कुछ धारदार लोग धड़ल्ले से कब्जा जमा रहे हैं। कब्जा जमाने वालों ने सरकारी नौकरी में आकर भी ट्रांसफर नीति को अपनी धार से बार-बार काट दिया। किसी सरकार में यह धार नहीं रही कि स्थानांतरण नियमों को पैना करे। अब तो राजनीति की धार भी कुंद है, क्योंकि न जाने कब कब कौन, सत्ता से विपक्ष और विपक्ष से सत्ता पक्ष हो जाए। अब धार नहीं राजनीति एक धारावाहिक है जहां चरित्र अपने लिए एपिसोड बना रहे हैं।

गुरदासपुर में पुलिस कर्मी के घर पर धमाका, बच्चर खालसा ने ली जिम्मेदारी

कांग्रेसी सांसद ने घटनास्थल की तस्वीरें की वायरल

चंडीगढ़ (हिंस)। पंजाब के सीमावर्ती जिला गुरदासपुर में बीती रात अतिक्रमों ने एक पुलिस कर्मी के घर को निशाना बनाकर धमाका किया है। पुलिस इस मामले में अधिकारित और पर कुछ नहीं बोल रही है लेकिन आतंकी संगठन बच्चर खालसा ने एक पोस्ट डालकर धमाके की जिम्मेदारी ली है। पंजाब में पुलिस थानों पर ही रहे हमलों व धमाकों की श्रृंखला में यह 12वां धमाका है। गुरदासपुर से कांग्रेसी सांसद सुखनिंदर सिंह रंधावा ने मंगलवार सुबह घटनास्थल का दौरा करके तस्वीरें भी वायरल कर दी हैं जानकारी के अनुसार गुरदासपुर जिले के अंतर्गत आरो डेराबाबा नानक विधानसभा हलके के गांव रायमल्ल में बीती रात जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका पुलिस



कर्मी जिंदिं सिंह के चाचा के घर पर हआ। अपूर्व सुन्नों के अनुसार बीती रात जिंदिं सिंह को यहां आया था। गली से किसी ने ग्रेनेडमाल कोई बहुत फेंकी जो खिड़की तोड़ते हुए घर के भीतर गिरे और जोरदार धमाका हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गुरदासपुर के एसएसपी

सुहेल कासिम मीर मौके पर पहुंचे और एकएसएल की टीमों ने वहां से सेंपल भरे। एसएसपी के अनुसार यह लोटैंसिटी धमाका था। जिसकी जांच रही रही थी कि बच्चर खालसा के अतिक्रम नहीं हुआ है। इसके कोई बदलत नहीं हुआ है। पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि बच्चर खालसा के अतिक्रम हैं। यहीं पासियां ने पोस्ट डालकर इसकी जिम्मेदारी ली। हेही पासियां के अनुसार यह धमाका शेरो मान की मदद से अंजम दिया गया है। पोस्ट में कहा गया है कि आज जो घटना गांव रायमल में जिंदिं पुलिस वाले के घर ग्रेनेड हमला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं, हेही पासियां और भाई शेरो मान लेता है। धमाके की घटना के बाद पंजाब के पूर्व डिस्ट्री सीएम एवं सांसद सुखनिंदर सिंह रंधावा परिवार से

मिलने पहुंचे। रंधावा ने धमाके वाले स्थान की तस्वीरें शोशल मीडिया एक्सप्लॉस साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को लिखा कि अगर हम से जुँझ रही है, जिससे प्रदेश के प्रभारी तक बढ़ता जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष की भी छुट्टी होने की संभावना जताहै जा रही है। योजीव जैन ने कहा कि कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि बहुत जांचों पर उड़े उम्मीदवार तक नहीं मिले। उड़े हुए गुड्डींडी, बूज्य हल्वाई हड्डी, ओल्ड रोहतक रोटी, जैन वारा कलीनी, चिल्ड्रन पार्क मॉडल टायर साहित कई स्थानों पर जनसभाएं की, जहां उनका गर्भजीसी से स्वागत किया गया। उड़े हुए वादा किया कि जनता के सहयोग से सोनीपत को खच्च नींवी की

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज भारत को 2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र बनाना हमारा विजय : सीआर पाटिल पेश करेंगी राजस्थान का बजट

सुरक्षित एवं समृद्ध भविष्य के लिए जल अत्मनिर्भरता बेहद महत्वपूर्ण : भजनलाल शर्मा



जयपुर (हिंस)। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी 19 फरवरी (बुधवार) को विधानसभा में वित्ती वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गोपनीय के वर्ष 2025-26 के बजट को अंतिम रूप दिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अंगोरा, प्रमुख सांसद सचिव (बजट) देवालीपां योगी, शासन सचिव (व्याप) नवीन जैन, शासन सचिव गजरव त्रुमारपाल गौतम, निदेशक (बजट) बुजेश किंगेर शर्मा उपस्थित हैं।

सरकारी स्कूल में खेलते-खेलते टैक में गिरीं तीन छात्राओं की मौत

बीकानेर (हिंस)। नोएडा इलाके के एक सरकारी स्कूल में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खेलते-खेलते तीन छात्राएं पानी के टैक (टांक) में गिर गईं। आसपास खेल रहे बच्चों ने तुरंत शिक्षकों को सूचित किया। लगभग आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उड़े बाहर निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉकर्सों ने उड़े मृत घोषित कर दिया। यह हादसा नोखा क्षेत्र के देवानाडा स्थित (केली गांव) राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार सुबह हुआ। खेले के दौरान प्रेग्नेंट (8) पुरी रेखाराम जाट, भारती पुरी आमराम जाट और रवीना पुरी बागाराम स्कूल परिसर में स्थित पानी के टैक के

मोटी ने स्वच्छता पर जोर दिया है तथा 12 करोड़ लोग लापान्त्रित हुए, साथ ही डायरीय जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। जल जीवन मिलन के तहत अब देश के 15 करोड़ लोगों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी के टैक से दो विदेशी वाटर कॉम्पनी के उद्योग समाजों में कही। भोपाल के बाद उदयपुर में देश भर के राज्य जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इसके लिए 2047 तक 20 लाख महिलाओं को किट एवं प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह, वर्षा जल संग्रहण के लिए कैच दे रेन का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कर्म भूमि से मात्रभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी अपेक्षा अपेक्षाओं में भूलत पुनर्वर्णन के लिए रिचार्ज बैल बनाने में योगदान दे रहे हैं। उड़े

मोटी ने स्वच्छता पर जोर दिया है तथा 12 करोड़ लोग लापान्त्रित हुए। इसमें 60 करोड़ लोग लापान्त्रित हुए, साथ ही डायरीय जैसी गंभीर बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। जल जीवन मिलन के तहत अब देश के 15 करोड़ लोगों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। पानी के टैक से दो विदेशी वाटर कॉम्पनी के उद्योग समाजों में कही। भोपाल के बाद उदयपुर में देश भर के राज्य जल मंत्रियों का दूसरा अखिल भारतीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इसके लिए कैच दे रेन का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कर्म भूमि से मात्रभूमि अभियान के माध्यम से प्रवासी अपेक्षा अपेक्षाओं में भूलत पुनर्वर्णन के लिए रिचार्ज बैल बनाने में योगदान दे रहे हैं। उड़े

सुचित किया था। इसीलिए बीकानेर के स्कूल परिसर में बान यह टैक जमाने में घर चली गई। अन्य छात्रों ने उड़े अपराधियों को एक घंटे के बाद उड़े बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विद्यालय की प्रधानाकारी ने 18 दिसंबर 2024 को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जर्जर पानी के टैक की स्थिति के बारे में लिखी गयी।

पूलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में चार कांग्रेस नेता उड़ित राज के बयान पर मायावती

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)। बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस)।

बीड़ीयोग्राफर पकड़े गए

फारविसगंग/अररिया (हिंस

ज्यादा पेन किलर के सेवन से लिवर-किडनी को हो सकता है नुकसान

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को अक्सर शारीरिक दर्द, सिरदर्द, जांबंदी का दर्द या मासपेशियों में खिंचाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जल्दी आराम पाने के लिए लोग बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर दवाएं ले लेते हैं। हालांकि, यह आदत सेहत के लिए काफी खतरनाक साथित हो सकती है। पेन किलर दवाएं, जिन्हें दर्दनिवारक दवाएं भी कहा जाता है, का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के करने से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेने के क्या नुकसान हो सकते हैं। पेन किलर दवाएं अगर ज्यादा मात्रा में ली जाएं, तो लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिवर शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पेन किलर लेने से लिवर पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिससे लिवर डैमेज हो सकता है। इसी तरह, किडनी भी शरीर से हानिकारक पदार्थों को फिल्टर करने का काम करती है, लेकिन ज्यादा पेन

किडनी

फेलियर तक की स्थिति पैदा हो सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेने से पेन संबंधी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसकी वजह से पेन में अल्प, गैस्ट्रिक और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। कुछ पेन किलर दवाएं पेन की लाइनिंग को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे इंटरनल ब्लाइंडिंग भी हो सकती है। यह समस्या गंभीर हो सकती है और अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ सकती है। बिना डॉक्टर की सलाह के बारे बारे पेन किलर लेने से शरीर में इन दवाओं के लिए रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि समय के साथ दवाओं का असर कम होने लगता है और दर्द से राहत पाने के लिए ज्यादा मात्रा में दवा लेने की जरूरत पड़ती है। यह किंडिशन दवाओं की लत का कारण भी बन सकती है। कुछ पेन किलर दवाएं, जैसे कि एनएसएआईडीएस (नॉन-स्टेरोइडल एटी-इंफ्लमेटरी ड्रास), दिल से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। ज्यादा दवाएं लेने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। खासकर उन लोगों

को जिन्हें पहले से ही दिल से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें इन दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर अलग-अलग तरह से दवाओं पर एफेक्ट करता है। बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेने से कुछ लोगों को एलर्जी, त्वचा पर रैशेज, सांस लेने में तकलीफ या अन्य गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ मामलों में यह स्थिति जनलेवा भी हो सकती है। कुछ पेन किलर दवाएं, जैसे कि

ओपिओइड्स, मेंटल हेलथ पर नेट्रोटिव प्रभाव डाल सकती हैं। इन दवाओं को ज्यादा लेने से चिंता, डिप्रेशन और नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही, इन दवाओं की लत लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर दवाएं लेने से बचना चाहिए। कुछ दवाएं बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और जन्मजात विकृतियों का कारण बन सकती हैं।



भारत में सोलो ट्रिप के लिए सबसे आकर्षक जगहें, एक बार जरूर जाएं



सोलो ट्रिप रोमांचक, सशक्त और जीवन बदलने वाली हो सकती हैं। अगर आप भी सोलो यात्रा करने का प्लान बना रही हैं, तो आप इन जगहों पर जरूर जाएं। यहां पर आपको विविध संस्कृतियों और लोगों की खोज कर सकती है और स्वयं से जुड़ सकती है। आजकल महिलाएं तेजी से सोलो ट्रिप का विकल्प चुन रही हैं क्योंकि दूर देशों की यात्राएं तनाव से राहत दिला सकती हैं और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता होती है। ये सोलो ट्रिप को अपनी इच्छाओं को खुलकर स्वीकार करने में मदद कर सकती हैं। अगर आप भी कहीं घूमने का प्लान बना रही हैं, तो इन जगहों पर जरूर जाएं।

ऋषिकेश : सोलो ट्रिप के लिए ऋषिकेश सरकरे बढ़िया जगहों में से एक है। यहां पर आप एडवेंचर एवं रिट्रिटीज कर सकते हैं। बंजी जंगिंग, रिकर रापिटग, बोट राफिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर आप गंगा आरती लाइव देख सकते हैं। ऋषिकेश में कई फैमस जगहें जहां आप जा सकते हैं जैसे कि परमार्थ निकेतन, निवेदी घाट और नीतकंठ मंदिर देखने जा सकते हैं।

पाडिचेरी : पाडिचेरी अपनी फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला, प्राचीन समृद्ध तरंगें और जीवंत कैफे संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। महिलाओं के लिए यह सुरक्षित टिकिना आकर्षण का बढ़ता है।

उदयपुर : उदयपुर सुखद अनुभव प्रदान करता है। अॉरोविले आश्रम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव प्रदान करता है।

शिलांग : उत्तर पूर्वी भारत की मनमोहक सुंदरता को देखने के लिए शिलांग बहुत ही यारी जाती है। यहां भैरव, शांत झीलें और गिरते झरने आत्मा को तरोताजा कर देते हैं। स्थानीय खासी संस्कृति और संगीत आकर्षण का बढ़ता है।



ASSAM BUDGET 2025-2026

“Artwork for your Budget Cover”

Assam Budget for Financial Year 2025- 2026

- 1 Green Budget**
Aligning public budgets with environmental and climate goals.
- 2 Gender Budget**
Fiscal policy and administration to promote gender equality.
- 3 Child Budget**
Substantially for the benefit of children.
- 4 Divyang Budget**
Stepping up to improve lives of people with disabilities.
- 5 Outcome Budget**
Linking a government's spending to the results it achieves.

Last date for submission 26 February, 2025

Resolution- 300 dpi | Canvas Size- 8x11 inches
No Age Limit

Send your artwork to-
inclusivebudgetassam@gmail.com

<https://finance.assam.gov.in> @assamfindept

